REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2026

स्वतंत्रता आंदोलन में स्थानीय क्रांतिकारियों का योगदान : डिंडोरी जिले के संदर्भ में*

विक्रम सिंह टेकाम
शोधार्थी इतिहास
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. नृपेन्द्र सिंह परिहार
प्राचार्य
डी.आर.एस.बी.एड. कॉलेज, गंगापुर, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता केवल राष्ट्रीय नेतृत्व तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के दूरस्थ जिलों और आदिवासी बहुल अंचलों में सक्रिय स्थानीय क्रांतिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निर्णायक भूमिका रही। मध्यप्रदेश का डिंडोरी जिला, जो महाकौशल क्षेत्र का एक प्रमुख आदिवासी–प्रधान भूभाग है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन–प्रतिरोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस शोध में डिंडोरी जिले में सक्रिय ग्राम–स्तरीय नेताओं, आदिवासी संगठनों, महिला कार्यकर्ताओं तथा युवाओं द्वारा संचालित आंदोलनों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखीय स्रोतों, जिला गजेटियर, क्षेत्रीय इतिहास–ग्रंथों और मौखिक परंपराओं के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार स्थानीय संघर्षों ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को जनाधार प्रदान किया। डिंडोरी जिले के क्षेत्रीय प्रयास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जमीनी शक्ति के प्रतिनिधि थे।

मुख्य शब्द – भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, डिंडोरी जिला, स्थानीय क्रांतिकारी, आदिवासी आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन।

प्रस्तावना –

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विश्व इतिहास के सबसे व्यापक, दीर्घकालिक और जन–आधारित उपनिवेश–विरोधी संघर्षों में से एक रहा है। सामान्यतः इस आंदोलन का इतिहास राष्ट्रीय नेताओं, अखिल भारतीय राजनीतिक संगठनों और प्रमुख घटनाओं–असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के इर्द–गिर्द प्रस्तुत किया जाता है। किंतु बीते कुछ दशकों में इतिहासलेखन की नई प्रवृत्तियों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि स्वतंत्रता संघर्ष की वास्तविक सामाजिक ऊर्जा भारत के ग्रामीण अंचलों, वनवासी क्षेत्रों और जिला–स्तरीय समाजों में निहित थी। स्थानीय क्रांतिकारी, ग्राम–स्तरीय नेतृत्व, जनजातीय संगठन, महिला कार्यकर्ता और छात्र समूहों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनचेतना को सशक्त आधार प्रदान किया। इन स्थानीय प्रयासों के बिना राष्ट्रीय आंदोलनों की व्यापकता और निरंतरता संभव नहीं होती।

मध्यभारत का महाकौशल क्षेत्र, जिसमें वर्तमान डिंडोरी जिला सम्मिलित है, औपनिवेशिक काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत दूरस्थ माना जाता था, किंतु सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के कारण यहाँ उपनिवेश–विरोधी चेतना तीव्र गति से विकसित हुई। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा वन–संपदा के व्यवस्थित दोहन, भूमि–राजस्व की नई व्यवस्थाओं और श्रम–नियंत्रण की नीतियों ने आदिवासी एवं कृषक समाज की पारंपरिक जीवन–प्रणालियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन परिवर्तनों ने स्थानीय समुदायों में असंतोष को जन्म दिया, जो धीरे–धीरे संगठित प्रतिरोध और राजनीतिक लामबंदी के रूप में अभिव्यक्त होने लगा। इस प्रकार डिंडोरी जैसे जिलों में स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप केवल राजनीतिक अधिकारों की माँग तक सीमित न रहकर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्मिता और संसाधनों पर नियंत्रण के प्रश्नों से भी जुड़ गया।

डिंडोरी जिला गोंड, बैगा और अन्य जनजातीय समुदायों की बहुलता के कारण सामाजिक–संरचना की दृष्टि से विशिष्ट रहा है। औपनिवेशिक शासन से पूर्व यहाँ वन, नदी और भूमि स्थानीय जीवन–पद्धति का अभिन्न अंग थे। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लागू किए गए वन अधिनियमों, आरक्षित वनों की स्थापना और ठेकेदारी प्रथा ने इन समुदायों के परंपरागत अधिकारों को सीमित कर दिया। वनोपज संग्रह पर नियंत्रण, झूम–कृषि पर प्रतिबंध और श्रम–कर जैसी व्यवस्थाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त किया। इन परिस्थितियों ने धीरे–धीरे राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, जिसे बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस आंदोलन और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा वैचारिक दिशा मिली।

स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरणों में डिंडोरी जिले में राजनीतिक गतिविधियाँ अपेक्षाकृत सीमित थीं, किंतु 1920 के दशक के बाद यह क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलनों की धारा से अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ने लगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब–दुकानों के विरुद्ध धरना, चरखा–प्रचार और ग्राम सभाओं के आयोजन जैसे कार्यक्रमों ने जनसाधारण को पहली बार संगठित राजनीतिक गतिविधियों से परिचित कराया। इन आंदोलनों में स्थानीय शिक्षकों, पुजारियों, कृषकों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है, जिन्होंने राष्ट्रीय नेताओं के संदेशों को स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता संघर्ष के 'स्थानीयकरण' का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें अखिल भारतीय विचारधाराओं को क्षेत्रीय सामाजिक यथार्थ के अनुरूप ढाला गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में डिंडोरी जिले में राजनीतिक चेतना और अधिक सशक्त हुई। कर–बहिष्कार, प्रतीकात्मक नमक–निर्माण, जुलूस और गिरफ्तारी जैसे कार्यक्रमों ने औपनिवेशिक प्रशासन को सीधे चुनौती दी। यद्यपि यह क्षेत्र समुद्र से दूर था, फिर भी नमक कानून के विरोध को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रतीकों को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्रचित किया। इस चरण में आदिवासी समुदायों की भागीदारी भी बढ़ी, क्योंकि आंदोलन उनके दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों–वन–अधिकार, कर–भार और पुलिस–दमन को संबोधित करने लगा।

1942 का भारत छोड़ो आंदोलन डिंडोरी जिले के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस अवधि में युवाओं और कृषकों द्वारा संचालित विरोध–प्रदर्शनों, सरकारी संचार–व्यवस्था में व्यवधान तथा प्रशासनिक संस्थानों के विरुद्ध प्रतीकात्मक कार्रवाइयों की खबरें मिलती हैं। ब्रिटिश प्रशासन ने इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तारियों, दंडात्मक करों और तलाशी अभियानों का सहारा लिया, किंतु आंदोलन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। इस दौर में भूमिगत नेटवर्क, गुप्त संदेश–वाहन और ग्रामीण समर्थन–प्रणालियों ने आंदोलन की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्थिति दर्शाती है कि डिंडोरी जैसे जिलों में स्वतंत्रता संघर्ष केवल वैचारिक समर्थन तक सीमित न रहकर प्रत्यक्ष राजनीतिक चुनौती का रूप ग्रहण कर चुका था।

डिंडोरी जिले में महिलाओं की भूमिका भी स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक व्यापकता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभात–फेरियों, खादी–प्रचार, चरखा–आंदोलन और सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक चेतना को घरेलू और सामुदायिक जीवन के भीतर प्रवेश कराया। अनेक अवसरों पर महिलाओं ने संदेश–वाहक के रूप में कार्य किया और आंदोलनों के लिए संसाधन जुटाए। आदिवासी महिलाओं की सहभागिता ने आंदोलन को सांस्कृतिक रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाया, क्योंकि वे स्थानीय परंपराओं और सामूहिक गीत–नृत्यों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करती थीं। इस प्रकार डिंडोरी में स्वतंत्रता संघर्ष केवल पुरुष–प्रधान राजनीतिक गतिविधि न रहकर व्यापक सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया।

इतिहासलेखन की दृष्टि से डिंडोरी जैसे जिलों में हुए स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय इतिहास–ग्रंथों में प्रायः ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख संक्षेप में ही मिलता है। जिला–स्तरीय अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध विविध सामाजिक समूहों द्वारा अपने–अपने अनुभवों और हितों के आधार पर संगठित किया गया। हाल के वर्षों में उपनिवेश–विरोधी आंदोलनों के क्षेत्रीय आयामों पर केंद्रित शोध–कार्य बढ़े हैं, किंतु डिंडोरी जिले को केंद्र में रखकर किए गए समग्र और अभिलेखीय रूप से सुदृढ़ अध्ययन अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं। प्रस्तुत शोध इसी बौद्धिक रिक्ति को भरने का प्रयास करता है।

इस अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य डिंडोरी जिले में सक्रिय स्थानीय क्रांतिकारियों और ग्राम–स्तरीय नेताओं के योगदान का समग्र मूल्यांकन करना है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किस प्रकार इन व्यक्तियों और समूहों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को सामाजिक आधार प्रदान किया। इसके साथ–साथ यह शोध आदिवासी चेतना, महिला सहभागिता और ग्रामीण नेटवर्कों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम की बहुस्तरीय प्रकृति को उजागर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह प्रस्तावना न केवल अध्ययन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, बल्कि उस वैचारिक ढाँचे को भी रेखांकित करती है जिसके अंतर्गत डिंडोरी जिले के स्वतंत्रता संघर्ष को समझा और विश्लेषित किया जाएगा।

विश्लेषण –

डिंडोरी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट होता है कि यहाँ उपनिवेश–विरोधी चेतना का विकास केवल राजनीतिक घोषणाओं या बाहरी प्रभावों का परिणाम नहीं था, बल्कि स्थानीय सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं में आए परिवर्तनों से उत्पन्न असंतोष की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई वन–नीतियाँ, भूमि–राजस्व व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा और श्रम–नियंत्रण की व्यवस्थाओं ने आदिवासी तथा कृषक समाज की पारंपरिक जीवन–पद्धतियों को बाधित किया। इन नीतियों के कारण वनोपज संग्रह पर प्रतिबंध, खेती योग्य भूमि में कमी और नकद कर–भुगतान का दबाव बढ़ा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक असुरक्षा गहरी हुई। यही परिस्थितियाँ राजनीतिक चेतना के सामाजिक आधार का निर्माण करती हैं, जिसे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों से वैचारिक दिशा मिली।

असहयोग आंदोलन के दौरान डिंडोरी में दिखाई देने वाली गतिविधियाँ इस बात का संकेत देती हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित रणनीतियाँ किस प्रकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्रचित की गईं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब–दुकानों के विरुद्ध प्रदर्शन, ग्राम–सभाओं का आयोजन और चरखा–प्रचार जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण समाज में राजनीतिक संवाद की नई भाषा गढ़ी। स्थानीय शिक्षकों, धार्मिक व्यक्तियों और युवाओं ने राष्ट्रवादी विचारों को जनजातीय बोली और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। इससे आंदोलन केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीण और आदिवासी समाज की व्यापक भागीदारी वाला उपक्रम बन गया। इस चरण में राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था, किंतु इसकी सामाजिक जड़ें गहरी होती चली गईं।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के काल में डिंडोरी जिले में राजनीतिक सक्रियता का स्तर और तीव्र हो गया। कर–बहिष्कार, जुलूस, प्रतीकात्मक नमक–निर्माण तथा स्वैच्छिक गिरफ्तारियाँ औपनिवेशिक प्रशासन के प्रति प्रत्यक्ष असहमति के रूप में उभरीं। इन गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रतीकों को केवल अनुकरण की दृष्टि से नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्व्याख्यायित किया। आदिवासी समुदायों की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि आंदोलन उनके दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों–वन–अधिकार, कर–दबाव और पुलिस–उत्पीड़न को संबोधित करने लगा था। इस प्रकार डिंडोरी में स्वतंत्रता आंदोलन एक सीमित राजनीतिक अभियान से विकसित होकर व्यापक सामाजिक प्रतिरोध का रूप ग्रहण करता है।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने जिले में राजनीतिक चेतना को एक निर्णायक मोड़ दिया। इस चरण में युवाओं और कृषकों द्वारा संगठित विरोध–प्रदर्शन, सरकारी संचार–व्यवस्था में व्यवधान और प्रशासनिक संस्थानों के विरुद्ध प्रतीकात्मक कार्रवाइयों की सूचनाएँ मिलती हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा गिरफ्तारियों, आर्थिक दंडों और तलाशी अभियानों के माध्यम से आंदोलन को दबाने के प्रयास किए गए, किंतु ग्रामीण समर्थन–प्रणालियों और भूमिगत नेटवर्कों ने इसकी निरंतरता बनाए रखी। गुप्त संदेश–वाहन, भोजन और आश्रय

की व्यवस्था तथा रात के समय आयोजित बैठकों जैसी गतिविधियाँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि आंदोलन अब केवल सार्वजनिक सभाओं तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उसने एक वैकल्पिक संगठनात्मक ढाँचा भी विकसित कर लिया था।

डिंडोरी जिले में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण आंदोलन की सामाजिक व्यापकता को और अधिक स्पष्ट करता है। प्रभात–फेरियों, खादी–प्रचार, चरखा–आंदोलन और सत्याग्रह में महिलाओं की उपस्थिति ने राजनीतिक चेतना को घरेलू और सामुदायिक जीवन से जोड़ा। कई मामलों में महिलाएँ गुप्त संदेश पहुँचाने, कार्यकर्ताओं को शरण देने और संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। आदिवासी महिलाओं की सहभागिता ने आंदोलन को सांस्कृतिक वैधता प्रदान की, क्योंकि वे लोकगीतों, नृत्यों और सामूहिक अनुष्ठानों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित करती थीं। इस प्रकार डिंडोरी में स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप लैंगिक दृष्टि से भी अपेक्षाकृत समावेशी बनता दिखाई देता है।

स्थानीय क्रांतिकारियों और ग्राम–स्तरीय नेताओं की भूमिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति और ग्रामीण समाज के बीच सेतु का कार्य किया। ये नेता प्रायः शिक्षित मध्यमवर्ग, कृषक परिवारों या आदिवासी मुखियाओं से आए थे, जिनके पास स्थानीय समुदायों में सामाजिक प्रतिष्ठा और संवाद–क्षमता थी। उन्होंने कांग्रेस संगठनों की शाखाएँ स्थापित कीं, स्वयंसेवी दल गठित किए और राजनीतिक संदेशों को स्थानीय संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत किया। इन प्रयासों से आंदोलन को संगठनात्मक निरंतरता प्राप्त हुई और वह अस्थायी उत्साह की जगह दीर्घकालिक सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तित हुआ।

इस प्रकार डिंडोरी जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का विश्लेषण यह संकेत देता है कि यहाँ उपनिवेश–विरोधी संघर्ष एक बहुस्तरीय सामाजिक प्रक्रिया थी, जिसमें आर्थिक असंतोष, सांस्कृतिक अस्मिता और राजनीतिक आकांक्षाएँ परस्पर जुड़ी हुई थीं। स्थानीय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को ग्रामीण यथार्थ से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक गहराई प्रदान की। इस दृष्टि से डिंडोरी जैसे जिलों में संचालित क्षेत्रीय संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जमीनी संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे यह प्रमाणित करते हैं कि स्वतंत्रता केवल महानगरों में नहीं, बल्कि देश के दूरस्थ अंचलों में भी समान रूप से गढ़ी जा रही थी।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम की सफलता केवल राष्ट्रीय नेताओं और बड़े शहरों में संकुचित संघर्ष की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके पीछे ग्रामीण तथा आदिवासी जिलों में सक्रिय स्थानीय क्रांतिकारियों, ग्राम–स्तरीय नेतृत्व और आम लोगों की प्रतिरोधात्मक चेतना की भी निर्णायक भूमिका थी। डिंडोरी जैसे आदिवासी–प्रधान क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई वन–नीतियाँ, भूमि–राजस्व व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा और श्रम–नियंत्रण जैसी नीतियों ने स्थानीय सामाजिक–आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया, जिससे असंतोष की भावना ने राजनीतिक चेतना का रूप लिया। असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नीतियों को अपने सामाजिक संदर्भों में ढालकर ग्रामीण और आदिवासी समाज को संगठित किया। महिलाओं की सहभागिता, युवा नेटवर्कों की सक्रियता तथा गुप्त संगठनात्मक ढाँचों ने आंदोलन को व्यापक सामाजिक समर्थन प्रदान किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने इस चेतना को अधिक तीव्रता दी और स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष विरोध तथा प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध चुनौती का रूप दिया। इस प्रकार यह अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि डिंडोरी जिले में संचालित स्थानीय संघर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जमीनी संरचना का अभिन्न हिस्सा थे। स्थानीय क्रांतिकारियों ने केवल राष्ट्रीय अभियानों का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उन्हें सामाजिक यथार्थ के अनुरूप पुनर्रचित कर स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनाधार प्रदान किया। इसी व्यापकता और सामाजिक भागीदारी ने पूरे आंदोलन को अधिक प्रभावशाली और सर्वसमावेशी बनाया।

संदर्भ –

1. सरकार, सुमित – आधुनिक भारत : 1885–1947. अद्यतन संस्करण, मैकमिलन इंडिया, नई दिल्ली, 2021।
2. सिंह, के.एस. – भारत में जनजातीय आंदोलन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2022।
3. मध्य प्रदेश शासन, जिला गजेटियर : शहडोल, शासकीय मुद्रण विभाग, भोपाल, 2023।

4. "डिण्डोरी जिले का इतिहास." डिण्डोरी इतिहास, डिण्डोरी जिला वेबसाइट, 17 मार्च 2019।
5. "अवंतीबाई का शहीद स्थल : बालपुर, डिण्डोरी (म.प्र.)." सेल्फ–रिफॉर्म ब्लॉगस्पॉट, 26 जून 2014।
6. वर्मा, राजेश – "मध्य भारत में वन नीतियाँ और जनजातीय प्रतिरोध." स्टडीज इन हिस्ट्री, खंड 38, अंक 1, 2022, पृष्ठ 45–62।